इंटरनेट शटडाउन का प्रभाव

प्रलिम्सि के लयि:

संयुक्त राष्ट्र मानवाधकिार उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR), #KEEPITON गठबंधन, वशि्व बैंक।

मेन्स के लयि:

इंटरनेट शटडाउन और उसके नहितिार्थ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र मानवाधकिार उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR) द्वारा इंटरनेट शटडाउन नामक एक रपिोर्ट प्रकाशति की गई: जसिमें इसके रुझान, कारण, कानूनी नहितिार्थ और मानवाधकिारों पर प्रभाव, वर्णति हैं तथा कहा गया है कि इंटरनेट बंद करने से लोगों की सुरक्षा और कल्याण प्रभावति होता है, सूचना प्रवाह में बाधा आती है और अर्थव्यवस्था को क्षतपिहुँचती है।

इंटरनेट शटडाउन:

- **परचिय:**
  - इंटरनेट शटडाउन के उपाय का उपयोग आमतौर पर तब कयिा जाता है जब नागरकि अशांतकिी स्थतिहिोती है, ताकसिरकारी कार्रवाइयों के संबंध में सूचनाओं के प्रवाह को अवरुद्ध कयिा जा सके।
  - शटडाउन में अक्सर इंटरनेट कनेक्टविटिी या प्रभावति सेवाओं की पहुँच को पूर्णतः प्रतबिंधति कयिा जाता है। हालाँकसिरकारें तेज़ी से बैंडवडि्थ को कम करने या मोबाइल सेवा को 2G तक सीमति करने का सहारा लेती हैं, जो नाममात्र की पहुँच बनाए रखते हुए इंटरनेट का सार्थक उपयोग करना बेहद मुश्कलि बना देती है।
  - दुनयिा भर की सरकारों ने कई कारणों का हवाला देते हुए इंटरनेट को बंद करने का सहारा लयिा है
  - इसके अलावा वीडयिो, लाइव प्रसारण और अन्य पत्रकारति कार्यों को साझा करना तथा देखना मुश्कलि हो जाता है, जन्हिें अक्सर नागरकि समाज आंदोलनों, सुरक्षा उपायों के साथ-साथ चुनावी कार्यवाही के दौरान आदेश दयिा जाता है और मानवाधकिारों की नगिरानी व रपिोर्टगि को गंभीर रूप से प्रतबिंधति करता है।
- **संबंधति अंतर्राष्ट्रीय ढाँचे:**
  - इंटरनेट शटडाउन कई मानवाधकिारों को गंभीर रूप से प्रभावति करता है, साथ ही यह अभवि्यक्तकिी स्वतंत्रता और सुरक्षा तथा लोकतांत्रकि समाजों की नींव में से एक व्यक्तकि पूर्ण वकिास के लयि अनविार्य शर्त की जानकारी तक पहुँच को त्वरति रूप से प्रभावति करता है।
  - यह नागरकि और राजनीतकि अधकिारों और अन्य मानवाधकिार उपकरणों (अर्थात् मानवाधकिारों की सार्वभौमकि घोषणा) पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध में गारंटीकृत अन्य सभी अधकिारों के लयि एक मानदंड है।
  - सतत वकिास लक्ष्य अन्यायपूर्ण प्रतबिंधों से मुक्त, सार्वभौमकि रूप से उपलब्ध और सुलभ इंटरनेट द्वारा कार्य करने के लयि राज्यों के मानवाधकिार दायत्विों को सुदृढ़ करते हैं।
  - संचार नेटवर्क में अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टविटिी की सुविधा के लयि स्थापति, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) मानकों को अपनाने पर कार्य करता है जो सुनश्चिति करता है कनिेटवर्क और प्रौद्योगकियिाँ आपस में जुड़ती हैं तथा इंटरनेट तक पहुँच में सुधार करने का प्रयास करती हैं।

प्रमुख नष्किर्ष:

- **वैश्वकि परदृश्य:**
  - दुनयिा का ध्यान खींचने वाला पहला बड़ा इंटरनेट शटडाउन वर्ष 2011 में मसि्र में हुआ था और इसके साथ ही सैकड़ों गरिफ्तारयिाँ और हत्याएँ भी हुई थीं।
  - #कीपइटऑन गठबंधन **(#KeepItOn coalition)**, जो दुनयिा भर में इंटरनेट शटडाउन एपसिोड की नगिरानी करता है, द्वारा वर्ष

2016-2021 तक 74 देशों में 931 शटडाउन का दस्तावेजीकरण किया गया।
    - उस अवधि के दौरान 12 देशों द्वारा 10 से अधिक शटडाउन लागू किये गए। वैश्विक स्तर पर सभी क्षेत्रों में कई शटडाउन का सामना किया गया है, लेकिन अधिकांश रिपोर्ट एशिया और अफ्रीका में हुई है।
    - नागरिक समाज समूहों द्वारा दर्ज किये गए शटडाउन में से 132 को आधिकारिक तौर पर अभद्र भाषा, दुष्प्रचार या अवैध या हानिकारक समझी जाने वाली सामग्री के अन्य रूपों के प्रसार को नियंत्रित करने की आवश्यकता द्वारा उचित ठहराया गया था।
- **भारतीय परिदृश्य:**
    - भारत ने इंटरनेट कनेक्शन को 106 बार अवरुद्ध या बाधित किया तथा भारत के कम-से-कम 85 इंटरनेट शटडाउन एपिसोड जम्मू और कश्मीर में हुए।
    - नागरिक समाज समूहों द्वारा वर्ष 2016-2021 तक दर्ज किये गए सभी शटडाउन में से लगभग आधे को विरोध और राजनीतिक संकटों के संदर्भ में किया गया था, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक शिकायतों की एक विशाल शृंखला से संबंधित सार्वजनिक प्रदर्शनों के दौरान 225 शटडाउन दर्ज किये गए थे।
- **चुनाव के दौरान शटडाउन:**
    - यह डिजिटल उपकरणों तक पहुँच को समाप्त करता है जो चुनाव प्रचार, सार्वजनिक चर्चा को बढ़ावा देने, मतदान करने और चुनावी प्रक्रियाओं की देख-रेख के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
    - अकेले वर्ष 2019 में 14 अफ्रीकी देशों ने चुनावी अवधि के दौरान इंटरनेट तक पहुँच को बाधित कर दिया।
    - ये व्यवधान निष्पक्ष पत्रकारों और मीडिया के काम को सामान्य रूप से बाधित करते हैं। युगांडा में शटडाउन ने हिंसक दमनकारी उपायों की रिपोर्टों के बीच वर्ष 2021 में चुनावों के मीडिया कवरेज को कमज़ोर कर दिया।
    - चुनावी अवधि के दौरान विरोध के बाद शटडाउन बेलारूस और नाइजर जैसे देशों में भी रिपोर्ट किये गए थे।
- **इंटरनेट शटडाउन का प्रभाव:**
    - **आर्थिक गतिविधियों पर:** यह सभी क्षेत्रों के लिये बड़ी आर्थिक लागत का कारण बनता है, वित्तीय लेनदेन, वाणिज्य और उद्योग को बाधित करता है।
        - विश्व बैंक ने हाल ही में गणना की है कि अकेले म्यांमार में इंटरनेट शटडाउन की लागत फरवरी-दिसंबर 2021 से लगभग 2.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जो पिछले दशक में हुई आर्थिक प्रगति को उलट देती है।
    - **शिक्षा पर:** यह सीखने के परिणामों को कमज़ोर करता है और शिक्षकों, स्कूल प्रशासकों, परिवारों के बीच शिक्षा योजना एवं संचार में हस्तक्षेप करता है।
    - **स्वास्थ्य और मानवीय सहायता तक पहुँच पर:**
        - अध्ययनों ने स्वास्थ्य प्रणालियों पर शटडाउन के महत्त्वपूर्ण प्रभावों को दिखाया है, जिसमें तत्काल चिकित्सा देखभाल जुटाना, आवश्यक दवाओं की डिलीवरी और उपकरणों के रखरखाव में बाधा डालना, चिकित्सा कर्मियों के बीच स्वास्थ्य सूचनाओं के आदान-प्रदान को सीमित करना और आवश्यक मानसिक स्वास्थ्य सहायता को बाधित करना शामिल है।
        - सहायता प्रदान करने के लिये मानवीय अभिकर्त्ताओं की क्षमता पर इंटरनेट शटडाउन का गहरा प्रभाव पड़ता है। आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं के वितरण के लिये महत्त्वपूर्ण सूचना के प्रवाह को बाधित किया जा सकता है।
            - म्याँमार में इंटरनेट शटडाउन ने कथित तौर पर स्थानीय सहायता संगठनों को संकट में डाल दिया, क्योंकि इसने उन्हें धन मांगने और प्राप्त करने से रोका था।

इंटरनेट शटडाउन हेतु भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश:

- जैसा कि अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ (2020) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फैसला दिया गया कि इंटरनेट शटडाउन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन नहीं करता है। यह एक उचित प्रतिबंध के रूप में कार्य करता है और इसे केवल तभी अधिनियमित किया जाना चाहिये जब सार्वजनिक सुरक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये कोई वास्तविक खतरा हो। कुछ संतुलन परीक्षण किये जाने चाहिये तथा केवल अत्यधिक आवश्यक होने पर ही सरकार को इस अत्यंत प्रतिबंधात्मक कदम का प्रयोग करना चाहिये।

आगे की राह

- रिपोर्ट में कहा गया है कि इंटरनेट शटडाउन की अधिक आवृत्ति की प्रवृत्ति को रोकने में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक उपायों और उनके प्रभावों की सीमित दृश्यता है।
- रिपोर्ट में राज्यों से शटडाउन से परहेज करने, इंटरनेट पहुँच को अधिकतम करने और संचार के रास्ते में कई बाधाओं को दूर करने का आग्रह किया गया है।
- इसने कंपनियों से व्यवधानों पर सूचनाओं को तेज़ी से साझा करने और यह सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया कि वे शटडाउन को रोकने के लिये सभी संभव कानूनी उपाय करें जिन्हें उन्हें लागू करने के लिये कहा गया है।
- शटडाउन डिजिटल डिवाइड को कम करने के प्रयासों, त्वरित आर्थिक और सामाजिक विकास के वादे को कमज़ोर करते हैं, जिससे सतत् विकास लक्ष्यों की उपलब्धि को खतरा होगा।

स्रोत: डाउन टू अर्थ

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/impact-of-internet-shutdowns